आरबीआई ने रेपो दर को रखा स्थिर

वित्तीय वर्ष में ईएमआई में कोई बदलाव नहीं किया गया है : रिजर्व बैंक

मुंबई, 08 अप्रैल.भारतीय रिजर्व बैंक ने पश्चिम एशिया संकट के बीच आपूर्ति श्रृंखला में आयी बाधाओं और मुद्रास्फीति बढ़ने की आशंका के बीच रेपो दर 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखी है.

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने बुधवार को समाप्त तीन दिन की बैठक में सर्वसम्मति से रेपो दर तथा दूसरी नीतिगत दरों को स्थिर रखने का फैसला किया.साथ ही केंद्रीय बैंक ने रेपो दर को लेकर अपना रुख तटस्थ बनाये रखा है.स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट पांच प्रतिशत और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेगी.

बैंकिंग तंत्र मजबूत बना हुआ है : संजय मल्होत्रा

मुंबई, रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को कहा कि देश का बैंकिंग तंत्र मजबूत बना हुआ है और एचडीएफसी बैंक के संचालन को कोई खामी नहीं पायी गयी है . श्री मल्होत्रा ने यहां मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एक प्रश्न के उत्तर में आश्वस्त किया कि देश का बैंकिंग तंत्र पूरी तरह से मजबूत बना हुआ है . पिछले दिनों एचडीएफसी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के इस्तीफे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बैंकों के निदेशक मंडल की बैठकों के विवरण की नियमित रूप से जांच की जाती है और हमारे हिसाब से एचडीएफसी बैंक के संचालन से संबंधित कोई खामी नहीं मिली है . उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में दिशा-निर्देशों में बदलाव की जरूरत नहीं लगती है . आरबीआई ने आज बैंकिंग तंत्र में सुधार के लिए कई उपायों की घोषणा की .

> वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ी है, शेयर बाजारों में व्यापक गिरावट दर्ज की गयी है, और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी बॉन्ड पर रिटर्न बढ़ गये हैं .उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति अभी नियंत्रण में है और लक्ष्य से नीचे है, लेकिन ईंधन की कीमतों में वृद्धि और मौसम से संबंधित संभावित व्यवधानों के कारण भविष्य में महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है .हालांकि खाद्य पदार्थों की कीमतें अभी स्थिर हैं, लेकिन भविष्य में अल नीनो जैसी परिस्थितियां जोखिम पैदा कर सकती हैं .

ईएमआई में कोई बदलाव नहीं हुआ है.घर, कार की ईएमआई स्थिर बनी रहेगी.

रुपया 16 पैसे टूटा

मुंबई, 08 अप्रैल.अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया मंगलवार को 16 पैसे टूट गया और कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 93.06 रुपये का बोला गया.पिछले कारोबारी दिवस पर भारतीय मुद्रा 28 पैसे की मजबूती के साथ 92.90 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई थी.रुपये पर आज शुरू से ही दबाव रहा.यह 15 पैसे गिरकर 93.05 रुपये प्रति डॉलर पर खुला.बीच कारोबार में यह ऊपर 92.87 रुपये और नीचे 93.12 रुपये प्रति डॉलर तक गया.विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की लगातार जारी बिकवाली ने रुपये पर दबाव बनाया.उन्होंने आज भारतीय पूंजी बाजार से शुद्ध रूप से 143.58 करोड़ डॉलर निकाले.

वीआईटी में शिक्षा से राष्ट्र निर्माण पर जोर

चेन्नई , 08 अप्रैल. चेन्नई के वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी ने मंगलवार को अपना यूनिवर्सिटी डे मनाया. इंडियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बिनोद कुमार इस मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे.

वीआईटी चेन्नई के पुराने स्टूडेंट मेजर वैभव चौरसिया गेस्ट ऑफ़ ऑनर के तौर पर शामिल हुए. इस इवेंट की अध्यक्षता वीआईटी के फाउंडर और चांसलर, डॉ. जी. विश्वनाथन ने की, और इस मौके पर वीआईटी के वाइस-प्रेसिडेंट डॉ. जी. वी. सेल्वम भी मौजूद थे. अपने भाषण में, श्री बिनोद कुमार ने स्टूडेंट्स को तेज़ी से बदलती दुनिया के लिए खुद को तैयार करने के लिए हिम्मत दी. उन्होंने चुनौतियों से निपटने और मौकों का फायदा उठाने के लिए लगातार कोशिश और एडजस्ट करने की क्षमता के महत्व पर ज़ोर दिया. उन्होंने एंड-यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर फोकस के साथ इनोवेशन की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया. ज्ञान और कैरेक्टर के रोल पर ज़ोर देते हुए, बिनोद कुमार ने कहा कि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुद को बनाने में मदद करेगी.

> मेजर वैभव चौरसिया ने स्टूडेंट्स से अपने आस-पास से इंस्पिरेशन लेने और पॉजिटिव असर पर फोकस करने की अपील की . उन्होंने उनसे हिम्मत बनाए रखने, सेल्फ-बिलीफ बनाए रखने की अपील की . उन्होंने कहा कि कभी हार मत मानो, कभी खुद पर शक मत करो . चीजें ठीक नहीं होंगी और चीजें गलत होंगी, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करते रहना होगा और हमेशा चीजें सही करनी होंगी . अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, डॉ . जी . विश्वनाथन ने एजुकेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर पर ज़ोर दिया .

महिलाएं बनीं भारत की क्रेडिट ग्रोथ की नई ताकत

नई दिल्ली, 08 अप्रैल. भारत की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका तेजी से बदल रही है और अब वे केवल घरेलू वित्त तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश के क्रेडिट मार्केट की एक मजबूत स्तंभ बनकर उभर रही हैं.

नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं अब रिटेल और बिजनेस लेंडिंग में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं, जिससे क्रेडिट ग्रोथ को नई दिशा मिल रही है. भारत में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहां वे क्रेडिट बाजार की महत्वपूर्ण चालक बनती जा रही हैं. नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि महिलाएं अब केवल छोटे कर्ज तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रिटेल और बिजनेस लोन के जरिए आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, देश में महिला उधारकर्ताओं का कुल क्रेडिट पोर्टफोलियो बढ़कर 76 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो कुल सिस्टम क्रेडिट का 26 प्रतिशत हिस्सा है. यह 2017 के 16 लाख करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 4.8 गुना वृद्धि को दर्शाता है, जो महिलाओं की बढ़ती वित्तीय भागीदारी का संकेत है.

उद्योग ने की सस्ती ऊर्जा-कर्ज की मांग

एल्युमिनियम भारत' पहल लॉन्च के लिए उद्योग ने मांगा समर्थन

नई दिल्ली, 08 अप्रैल. एल्युमिनियम एक्सट्रुजन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एलेमाई) ने मंगलवार को एल्युमिनियम भारत पहल की घोषणा की और सरकार से निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए सस्ती ऊर्जा एवं कर्ज तथा करो में रियायत की मांग की.

उद्योग जगत इसी वर्ष सितंबर में अहमदाबाद में एक बड़ी प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है.इस पहल का उद्घाटन वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने यहां संगठन के एक कार्यक्रम में किया.इस मौके पर श्री प्रसाद ने वैश्विक व्यापार में आ रहे परिवर्तनों के बीच स्थानीय उत्पाद क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर कहा कि एल्युमिनियम भारत पहल यह दिखाती है कि भारत एल्युमिनियम निर्माण में वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ना चाहता है.

> पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है, जिससे एल्युमिनियम जैसे ऊर्जा-आधारित उद्योग पर सीधा असर पड़ रहा है .इसके अलावा उत्पादकों के लिए परिवहन लागत और सप्लाई चेन की समस्याएं भी बढ़ गई हैं .दूसरी ओर भारत में खास कर एल्युमिनियम स्क्रैप की कमी है जिसके कारण कच्चे माल की लागत दुनिया में सबसे अधिक है, जो डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए अत्यंत जरूरी है .

सरकार भारतीय उद्योग को समान अवसर देने और भारत को उच्च गुणवत्ता वाले एल्युमिनियम उत्पादों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

देश में 24 दिन का कोयला बैकअप

नई दिल्ली, 8 अप्रैल. दुनियाभर में भू-राजनीतिक तनाव और ऊर्जा संकट की खबरों के बीच भारत सरकार ने आम जनता और उद्योगों को भरोसा दिलाया है कि देश में न बिजली की कमी होगी और न रसोई गैस या पेट्रोल-डीजल की. कोयला, पेट्रोलियम और विदेश मंत्रालय की संयुक्त जानकारी के मुताबिक, देश के पास पर्याप्त ऊर्जा भंडार मौजूद है और बिजली, गैस तथा ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सुनिश्चित की गई है. कोयला मंत्रालय ने बताया देश में वर्तमान में 55 मिलियन टन कोयले का भंडार मौजूद है, जो अगले 24 दिनों तक पूरी बिजली आपूर्ति के लिए पर्याप्त है. औद्योगिक इकाइयों के लिए नए नियम और आपूर्ति प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर घरेलू उपभोक्ताओं की आपूर्ति प्रभावित न हो.

सीजफायर के बावजूद सोना-चांदी में 6 प्रतिशत का उछाल

नई दिल्ली 08 अप्रैल. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दो सप्ताह के सीजफायर प्लान की घोषणा के बावजूद बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला. सुरक्षित निवेश (सेफ-हेवन) की मांग बढ़ने से कीमती धातुओं में तेजी बनी रही.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना और चांदी दोनों ने ऊंचे स्तर छुए हैं. सोना 1.53 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया, जबकि चांदी में करीब 6 प्रतिशत तक की तेज बढ़त दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के जून 5 फ्यूचर्स 3,688 रुपये या 2.45 प्रतिशत बढ़कर 1,53,977 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए (सुबह 10:52 बजे तक). सोना 1,53,920 रुपये पर कारोबार करता दिखा, जो 3,631 रुपये या 2.42 प्रतिशत की बढ़त है. इसका इंट्राडे लो 1,53,301 रुपये रहा, जो पिछले बंद के मुकाबले 2 प्रतिशत ऊपर है. वहीं, चांदी के मई 5 फ्यूचर्स में करीब 6 प्रतिशत या 13,422 रुपये की तेजी आई और यह 2,44,770 रुपये के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया. आखिरी अपडेट तक चांदी 2,44,297 रुपये पर कारोबार कर रही थी,

फार्मा, फूड और कृषि जैसे क्षेत्रों को मिलेगी राहत

उद्योगों को मिलेगा 70 प्रतिशत आवंटन

नई दिल्ली, 08 अप्रैल. केंद्र सरकार ने एलपीजी आवंटन के लिए नया फॉर्मूला लागू कर दिया है, ताकि फार्मा, फूड, कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए अहम सेक्टर्स को पर्याप्त एलपीजी मिल सके.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार अब इन उद्योगों को उनकी मार्च 2026 तक की खपत का 70 प्रतिशत एलपीजी मिलेगा. हालांकि, पूरे सेक्टर के लिए कुल सीमा 0.2 टीएमटी

प्रतिदिन तय की गई है. नए फॉर्मूले में प्राथमिकता उन फैक्ट्रियों को दी गई है, जहां एलपीजी की जगह प्राकृतिक गैस का उपयोग संभव नहीं है. इसके लिए उद्योगों को तेल कंपनियों के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा और पाइप्ड नेचुरल गैस के लिए आवेदन करना होगा. हालांकि, जहां गैस उपलब्ध नहीं है, वहां पीएनजी आवेदन की शर्त नहीं लागू होगी. सरकार ने इस योजना से उद्योगों की उत्पादन क्षमता और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है. नए फॉर्मूले से एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होगी और महत्वपूर्ण उद्योगों को उत्पादन में रुकावट से बचाया जाएगा. सरकार द्वारा राज्यों को पहले ही पैक्ड नॉन-डोमेस्टिक एलपीजी का 70 प्रतिशत आवंटन किया जा चुका है. इसमें 10 प्रतिशत का अतिरिक्त कोटा उन राज्यों को मिलेगा जो पीएनजी से जुड़े तय सुधार लागू करेंगे.

रेयर अर्थ मैग्नेट निर्माण को बढ़ावा

7,280 करोड़ की योजना से मैग्नेट सेक्टर को रफ्तार

नई दिल्ली, 08 अप्रैल. देभारत सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है, जो देश को इस रणनीतिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

एक के तहत 7,280 करोड़ रुपये की योजना पर काम तेज हो गया है, जिसके लिए हाल ही में प्री-बिड कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई. इस योजना का उद्देश्य देश में रेयर अर्थ मैग्नेट के पूरे उत्पादन चक्र को विकसित करना है—कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद तक. इसमें 25 कंपनियों ने हिस्सा लिया, जो इस क्षेत्र में बढ़ती रुचि को दर्शाता है. रेयर अर्थ मैग्नेट इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा जैसे अहम क्षेत्रों के लिए बेहद जरूरी होते हैं.

ऐसे में यह पहल न केवल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगी, बल्कि आयात पर निर्भरता कम करने और भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे लाने में भी मदद करेगी. इस योजना के तहत अधिकतम पांच कंपनियों का चयन किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक कंपनी 1,200 मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता वाली इकाई स्थापित करेगी.

वस्त्र उद्योग को 350 अरब का लक्ष्य

टेक्सटाइल सेक्टर को मिली नई रफ्तार

इंडिया हैंडमेड' को ग्लोबल पहचान देने पर जोर

नई दिल्ली 08 अप्रैल.केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने मंगलवार को कहा कि भारत का वस्त्र उद्योग 2030 तक 350 अरब डॉलर तक बढ़ने के लिए तैयार है, जिसमें निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है.

उन्होंने नवाचार को बढ़ावा देने, योजनाओं में समन्वय को मजबूत

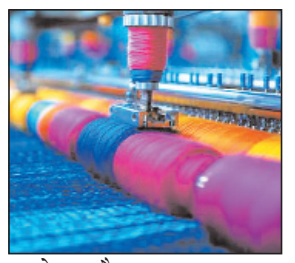

करने और एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता पर बल दिया जो लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है और सतत विकास का समर्थन करता है.सुश्री राव ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर उत्तरी क्षेत्र के हितधारकों के साथ परामर्श के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बैठक के समापन सत्र को संबोधित कर रही थीं.

इस बैठक में राज्य सरकारों, उद्योग निकायों, उद्यमियों, शिक्षाविदों, वस्त्र अनुसंधान संघों, निर्यात संवर्धन परिषदों और पुरस्कार विजेता बुनकरों और कारीगरों सहित 200 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया.सुश्री राव ने कहा कि बजट में प्रस्तावित योजनाएं विनिर्माण को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने पर केंद्रित हैं, और मूल्य श्रृंखलाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हैं.

समाचार विशेष

'ब्राह्मण-मुक्त' हुई तमिलनाडु की सियासत!

जयललिता की पार्टी ने भी मोड़ लिया मुंह, क्या खत्म हो जाएगा वजूद?

चेन्नई. तमिलनाडु की राजनीति, जिसे 'सामाजिक न्याय की प्रयोगशाला' कहा जाता है, इस बार एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक समय का सबसे प्रभावशाली समुदाय चुनावी मैदान से लगभग गायब नजर आ रहा है.

राज्य की चारों बड़ी पार्टियों- डीएमके, एआईडीएमके, कांग्रेस और भाजपा ने अपनी कैंडिडेट लिस्ट में ब्राह्मण समुदाय को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है. यह पिछले साढ़े तीन दशक में पहली बार है कि मुख्यधारा की राजनीति में ब्राह्मणों की ऐसी 'बेरुखी' देखी जा रही है. अब तमिलनाडु में जातीय समीकरण और 'जीतने की क्षमता' अब केवल बड़ी आबादी वाले समुदायों के इर्द-गिर्द सिमट गई है.

सबसे ज्यादा चर्चा एआईएडीएमके के रुख को लेकर हो रही है. कभी इस पार्टी को ब्राह्मण समुदाय का सबसे मजबूत समर्थन प्राप्त था और पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता खुद इसी समुदाय से आती थीं. उनके समय में ब्राह्मण उम्मीदवारों को हमेशा तवज्जो दी जाती थी, लेकिन उनके निधन के 10 साल बाद पार्टी की रणनीति पूरी तरह बदल गई है. साल 2021 के चुनाव में पार्टी ने कम से कम एक ब्राह्मण उम्मीदवार (आर. नटराज) को मैदान में उतारा था, लेकिन इस बार वह भी नदारद हैं. विश्लेषकों का मानना है कि जयललिता के बाद ब्राह्मण मतदाताओं का झुकाव भाजपा की ओर बढ़ गया है, जिससे अब एआईएडीएमके को इस समुदाय को टिकट देने में कोई 'चुनावी लाभ' नजर नहीं आ रहा है.

सिर्फ छोटे दलों ने थामा 'ब्राह्मणों' का हाथ

एक तरफ जहां बड़ी पार्टियों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं, वहीं कुछ नई और छोटी पार्टियों ने इस समुदाय को साधने की कोशिश की है . अभिनेता विजय की पार्टी 'तमिलागा वेट्री कषगम' ने 2 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया है . वहीं, तमिल राष्ट्रवादी नेता सीमन की पार्टी 'नाम तमिलर काचि' (एनटीके) ने सबसे ज्यादा 6 ब्राह्मण उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं . इन उम्मीदवारों को मायलापुर और श्रीरंगम जैसी सीटों पर उतारा गया है, जहां ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है . सीमन की इस रणनीति को 'द्रविड़ दीवार' को गिराने की एक वैचारिक कवायद के रूप में देखा जा रहा है .

गौरव गोगोई पर खामोश रहे हिमंता

गुवाहाटी. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा कांग्रेस के निशाने पर हैं. चुनाव प्रचार बंद होने से दो दिन पहले कांग्रेस ने उनकी पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के तीन पासपोर्ट का बम फोड़ा और साथ ही अमेरिका के टैक्स हेवन राज्य वायोमिंग में 52 हजार करोड़ रुपए की कंपनी होने का दावा किया.

कहा गया कि कंपनी में हिमंता और उनके बच्चे भी हिस्सेदार हैं. इसे लेकर बड़ा विवाद शुरू हुआ है और हिमंत बिस्वा सरमा और उनकी पत्नी ने कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी पवन खेड़ा को कानूनी नोटिस भेजने का ऐलान किया है.

लेकिन इस पूरे प्रकरण मे यह बहुत दिलचस्प मामला है कि हिमंता खुद गौरव गोगोई की पत्नी के पाकिस्तानी लिंक का आरोप लगाते रहे हैं और अभी अचानक खामोश हो गए हैं. उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि वे बड़े सबूत पेश करेंगे. लेकिन चुनाव प्रचार बंद होने तक भी उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया और न कोई सबूत पेश किया. उलटे इस मामले में वे खामोश हो गए. कहा जा रहा है कि यह भाजपा की रणनीति का हिस्सा है.

बदलती राजनीति की नई तस्वीर

महिला मोर्चा में पहली बार बनी वेल एजुकेटेड टीम

जयपुर. राजस्थान की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लगातार मजबूत होती जा रही है अब इसमें शिक्षित महिलाओं की भूमिका खास तौर पर उभरकर सामने आ रही है.

प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की नई टीम इसका ताजा उदाहरण है, जहां पढ़ी-लिखी और उच्च शिक्षित महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है. महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ की ओर से हाल ही में जारी की गई प्रदेश कार्यकारिणी सूची में बड़ी संख्या में ऐसी महिलाओं को शामिल किया गया है जो विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं.

राजस्थान की राजनीति में महिलाओं का यह दबदबा उनके एजुकेशन बैकग्राउंड के चलते बढ़ रहा है. प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा में शामिल टीम को देखने से साफ जाहिर हो रहा है कि मोर्चे के अध्यक्ष राखी राठौड़ की टीम में एक से बढ़कर एक शिक्षित महिलाओं को शामिल किया गया है. इस टीम में एमए, एमबीए, एलएलबी, पीएचडी, एमबीबीएस, बीडीएस और इंजीनियरिंग जैसी उच्च डिग्रियां रखने वाली महिलाओं को बड़ी संख्या में जगह दी गई है. अगर महिला मोर्चा की सूची पर नजर डालें तो प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर प्रवक्ता और आईटी संयोजक तक हर पद पर शिक्षित चेहरों का वर्चस्व दिखता है.

राठौड़ खुद एलएलबी, एलएलएम और एमएससी- मोर्चे की प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ खुद एलएलबी, एलएलएम और मैथ्स में एमएससी की डिग्री रखती हैं. वहीं डॉ. रजनी गावड़िया (एणबीबीएस, एमएस), डॉ. अंजली यादव (एलएलएम, पीएचडी), डॉ. नीलम मूंदड़ा (पीएचडी), डॉ. मंजू मेघवाल (पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी) जैसी महिलाएं इस टीम का हिस्सा हैं. वहीं आईटी, सोशल मीडिया और रिसर्च जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी टेक्निकल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड वाली महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है.

संगठन को नई सोच और ऊर्जा मिलेगी

बकौल राखी राठौड़ घर का मैनेजमेंट को संभालने वाली महिला को शासन चलाने की कमान मिलेगी तो वो बहुत शानदार सफलता के साथ काम करेगी . प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप शिक्षित महिलाओं के जुड़ने से संगठन को नई सोच और ऊर्जा मिलेगी . इससे न केवल महिला मोर्चा की कार्यप्रणाली मजबूत होगी, बल्कि समाज में भी सकारात्मक संदेश जाएगा कि महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व करने में सक्षम हैं . भाजपा महिला मोर्चा का यह कदम आने वाले समय में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को और अधिक बढ़ावा दे सकता है .

विशेष | **बीजेपी के प्रदर्शन से बदल सकते हैं समीकरण**

लौटेगी सत्ता परिवर्तन परंपरा या बनेगा नया इतिहास

तिरुवनंतपुरम. केरल विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राज्य एक बार फिर सत्ता परिवर्तन की अपनी पुरानी परंपरा की ओर लौटेगा या फिर मतदाता मौजूदा सरकार को लगातार तीसरी बार चुनकर इतिहास रचेंगे. लंबे समय से यहां की राजनीति दो प्रमुख गठबंधनों के बीच केंद्रित रही है.

एक सीपीआईएम के नेतृत्व वाला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और दूसरा और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाथ में है. केरल

के चुनावों में दोनों गठबंधन हर पांच साल में बारी-बारी से सत्ता में आते रहे हैं. लेकिन 2021 में एलडीएफ की लगातार दूसरी जीत ने इस चक्र को तोड़ दिया. पिनाराई विजयन से पहले राज्य में कोई भी मुख्यमंत्री लगातार दस साल तक सत्ता में नहीं रहा था. कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार चुनाव में यूडीएफ को बढ़त मिल सकती है. क्योंकि एलडीएफ को एक दशक की सत्ता-विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है. 2024 के लोकसभा चुनावों में यूडीएफ ने शानदार प्रदर्शन किया था. उसने यहां की 20 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी. इसी के साथ यूडीएफ के वोट शेयर में भी भारी इजाफा हुआ था. 2025 के स्थानीय निकाय चुनावों में भी उसके मजबूत प्रदर्शन ने इस धारणा को और बल दिया है कि इस बार सत्ता परिवर्तन संभव है. हालांकि, गहराई से देखने पर तस्वीर उतनी सरल नहीं लगती.

दरअसल, पिछले तीन दशकों में (2004 को छोड़कर) लोकसभा चुनावों में यूडीएफ का प्रदर्शन एलडीएफ से बेहतर रहा है. इसलिए 2019 और 2024 की जीत को एक दीर्घकालिक प्रवृत्ति का हिस्सा माना जाना चाहिए. लोकसभा चुनाव में मतदाता राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस-नेतृत्व वाले गठबंधन को प्राथमिकता देते हैं. यही कारण है कि लोकसभा के नतीजों को सीधे विधानसभा चुनावों का संकेत मानना सही नहीं होगा. यह कांग्रेस के लिए चिंता का विषय भी है, क्योंकि हाल के वर्षों में उसने उन राज्यों में विधानसभा चुनाव हारे हैं जहाँ उसे पहले संसदीय बढ़त मिली थी.

बीजेपी के पिछले प्रदर्शन से रोचक हुआ मुकाबला

इसी बीच, केरल में बीजेपी का पिछला प्रदर्शन चुनाव को और रोचक बना रहा है . अब तक तीसरे स्थान पर रहने वाली बीजेपी ने पिछले दशक में अपने वोट शेयर में लगातार वृद्धि की है . 2024 में उसने त्रिशूर लोकसभा सीट जीती . वो तिरुवनंतपुरम में दूसरे स्थान पर रही और कई अन्य क्षेत्रों में भी शानदारप्रदर्शन किया . 2025 के स्थानीय निकाय चुनावों में उसने पहली बार तिरुवनंतपुरम मेयर का पद जीतकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई .